E-Learning Study Material

By - Prof (Dr) YADWENDRA SINGH
MAHARAJA COLLEGE, ARA
V.K.S. UNIVERSITY, ARA, BIHAR

B.A. Economics Hons, Second Year
Paper third.

Main Features of Industrial Policy of 1956 of India :-

(ग) तृतीय श्रेणी में शेष सभी उद्योगों को रखा गया है जिनका भावी विकास सामान्यतः निजी क्षेत्र के उत्साह व प्रयत्नों पर छोड़ दिया जायगा :- इस श्रेणी के उद्योगों का विकास निजी क्षेत्र में होगा लेकिन आवश्यकता पड़ने पर राज्य भी इस क्षेत्र में कारखाना खोल सकता है। इस क्षेत्र में मुख्यतः सीमेन्ट, कागज, चीनी, सूती व ऊनी वस्त्र, वनस्पति, जूट आदि उद्योग आते हैं। इस श्रेणी में उद्योगों के विकास के लिए सरकार बिजली, यातायात व साख सुविधाएँ प्रदान करेगी। यही नहीं उचित कर प्रणाली द्वारा सरकार इनका विकास भी करेगी।

Scanned with CamScanner

2. लघु एवं कुटीर उद्योग धंधों का विकास :-
इस औद्योगिक नीति में लघु एवं कुटिर उद्योग धंधों के महत्व को विशेष रूप से स्वीकारा गया है। सरकार वृहत पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान करने, स्थानीय श्रमशक्ति और संसाधनों का उपयोग करने और औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए कुटीर एवं लघु उद्योगों की भूमिका पर जोर दिया। इसमें कहा गया है कि सरकार कर रियायतों और सब्सिडी के माध्यम से ऐसे उद्योगों का समर्थन करने की नीति जारी रखेगी साथ ही इन उद्योगों में नई तकनिक का प्रयोग कर इनकी प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति बढ़ा दी जायगी। इस क्षेत्र में सहकारी संगठन प्रोत्साहित होंगे।

3. क्षेत्रीय औद्योगिक विषमता को दूर करना :-
औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से क्षेत्रीय विषमता को दूर कर क्षेत्रीय संतुलन की व्यवस्था करना इस औद्योगिक नीति का एक प्रमुख उद्देश्य था। इसके लिए सरकार औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में शक्ति के साधन, जल यातायात, आदि सुविधाओं का विकास करेगी।

4. औद्योगिक शान्ति - प्रस्ताव के अनुसार उद्योग में लगे सभी पक्षों को उचित प्रोत्साहन दिया जायगा ताकि औद्योगिक शान्ति

स्थापित की जा सके। इसके लिए श्रमिकों के कार्य करने तथा रहन सहन की आवश्यकताओं की पूर्ति पर ध्यान देना तथा उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

5. तकनीकी एवं प्रबन्ध सम्बन्धी योग्यता एवं प्रशिक्षण की सुविधाएँ :- इस नीति में औद्योगिक विकास की आवश्यकताओं को देखते हुए तकनीकी एवं प्रबन्ध सम्बन्धी कर्मचारियों के विशेष वर्ग बनाने तथा कर्मचारियों के विशेष प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है।

6. सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र की अन्तर्निर्भरता पर जोर - इस नीति में सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के बीच अन्तर्निर्भरता का सम्बन्ध स्थापित किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग अपने उपभोक्ता और कच्चे माल सम्बन्धी वस्तुओं को निजी क्षेत्र से प्राप्त कर सकते है। और नीति क्षेत्र के उद्योग यंत्रों आदि वस्तुओं की पूर्ति के लिए सार्वजनिक क्षेत्र पर निर्भर रहेंगे।

7. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का प्रबन्ध :- इस नीति के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों के अधिकार एवं प्रबन्ध का व्यवसायिक सिद्धान्तों के आधार पर विकेन्द्रीकरण करने की सिफारिश की गयी है तथा इसके फलस्वरूप सरकारी आय में वृद्धि की संभावना व्यक्त की गयी है

Scanned with CamScanner

आलोचनाएँ :- 1956 की औद्योगिक नीति पर विभिन्न पक्षों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएँ व्यक्त की हैं: इस नीति को कुछ लोगों ने औद्योगिकरण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घोषणा कहा है इसके महत्व के कारण कुछलोगों ने तो इसे आर्थिक संविधान की संज्ञा दी है। सरकारी क्षेत्र के द्वारा इसे क्रान्तिकारी कदम बताया गया है - लेकिन कुछ अन्य विचारकों एवं उद्योगपतियों ने कई आधारों पर इस नीति की कटु आलोचना की है, कुछ प्रमुख आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं :-

(i) राष्ट्रीयकरण की धमकी अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान :- उपरी तौर पर देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह नीति निजी क्षेत्र के प्रति अधिक उदार है। परन्तु वस्तुतः इस नीति द्वारा निजी क्षेत्र को संकुचित करने का प्रयत्न किया गया है। इस नीति में राष्ट्रीयकरण की धमकी अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है। औद्योगिक नीति का यह वाक्य - "किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान को अर्जित करने के लिए राज्य की अन्तर्निहित शक्ति हमेशा विद्यमान रहेगी (inherent right of the State to aquire and industrial undertaking would always remain)" इस तथ्य की ओर पर्याप्त संकेत देता है।

Scanned with CamScanner

(ii) उद्योगों के विभाजन में नमनीयता के दुरुपयोग का भय :- इस नीति के प्रस्ताव में लोच पर जोर दिया गया है परन्तु इसका प्रयोग 'सार्वजनिक क्षेत्र' के लिए किया जायगा क्योंकि सरकार किसी भी उद्योग को प्रारम्भ कर सकती है। इस प्रकार अनुसूची 'ब' के उद्योगों के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों का स्थान गौण रहेगा और तृतीय श्रेणी के उद्योगों में भी सरकार का दखल रहेगा।

(iii) सहकारिता के नाम पर राजकीय पूँजीवाद को बढ़ावा :- सहकारी कृषि के विस्तार की सुविधा इस नीति में दिया गया है जो भ्रामक है। वस्तुतः सहकारी क्षेत्र सरकार के निर्देश पर ही काम करेगा और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों स्थान हमेशा गौण रहेगा। इस प्रकार भारत में सहकारिता के नाम पर राजकीय पूँजीवाद को बढ़ावा देने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(iv) व्यवहारिकता से अलग पूर्णतः सैद्धान्तिक नीति :- यह नवीन नीति वास्तविकता पर आधारित न होकर सिद्धान्तों एवं आदेशों पर अधिक आधारित है। निजी क्षेत्र की प्रगति को ध्यान में रख कर इसको अधिक महत्व दिया जाना चाहिए था किन्तु सरकार ने समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के आवेश में आकर वास्तविकता को भुला दिया है। समाजवादी समाज की स्थापना उद्योगों के

पूर्ण राष्ट्रीयकरण से नहीं बल्कि निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के आपसी सामंजस्य से होगा। इसके लिए सरकार को औद्योगिक नीति के व्यवहारिक पक्ष पर ध्यान देना होगा।

(v) सार्वजनिक क्षेत्र का आवश्यकता से अधिक विस्तार:- आलोचकों के अनुसार इस नीति में निजी क्षेत्र के क्रियाकलाप को बहुत सीमित कर दिया गया है।

(vi) नौकरशाही अत्याचार का भय :- सार्वजनिक उद्योग में भी निजी क्षेत्र की तरह नौकरशाही विद्यमान रहती है क्योंकि यहाँ भी राजनेताओं तथा बड़े पदाधिकारियों का आधिपत्य होता है जो तरह तरह से कर्मचारियों तथा मजदूरों का शोषण करते हैं।

(vii) विदेशी पूँजी के विषय में प्रस्ताव में कोई व्यवस्था नहीं की गयी। यदि इसके सम्बन्ध में नीति स्पष्ट होती तथा राष्ट्रीयकरण का क्षेत्र निश्चित कर दिया गया होता तो विदेशी पूँजीपति शंका मुक्त होकर भारत में अधिक पूँजी विनियोजित कर सकते थे। श्री मुन्नि ओलेक ने कहा कि - "यदि इस नीति का पालन दृढ़ता से किया गया तो लोकक्षेत्र के वित्तीय एवं प्रशासनिक दायित्वों पर जिन पर पहले से ही भार है और अतिरिक्त भार पड़ेगा तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास की गति सीमित हो जायगी।"

उपरोक्त 1956 की औद्योगिक नीति की आलोचना उपरोक्त आधारों पर की जाती है। इन समस्त आलोचनाओं का निचोड़

या निष्कर्ष नहीं है कि इस नीति में निजी क्षेत्र को संकुचित करके सार्वजनिक क्षेत्र का अधिक से अधिक विस्तार किया गया है। किन्तु इसकी गहराई में प्रवेश करने पर यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इस नीति के विरुद्ध की गयी आलोचनाएँ तथ्यहीन व निराधार हैं। देश की तत्कालीन परिस्थितियों को मद्दे नजर रखते हुए इससे अधिक सुनिश्चित व ठोस औद्योगिक नहीं बनाई जा सकती थी। क्योंकि इसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों को फलने फूलने का अवसर प्रदान किया गया। यह औद्योगिक नीति न तो पूर्णतः पूँजीवादी है न पूर्णतः समाजवादी बल्कि एक मध्यम मार्ग है जिसमें न तो पूँजीवादी प्रणाली की तरह शोषण की संभावना है और नहीं साम्यवादी प्रणाली की तरह मानवता का हनन। इसमें प्रजातंत्रात्मक समाजवाद (Democratic Socialism) की स्थापना पर बल दिया गया है।